

कार्यवाही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही

दस्तावेज फेकने पर बीएलओ निलंबित

अनूपपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 87-अनूपपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 31 जमुड़ी की बीएलओ राजकुमारी सिंह को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के दस्तावेजों को फेकने व लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोली ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संकुल केन्द्र शा. उ.मा.वि. सकरा के प्राथमिक शाला खीरापटपर की संविदा शिक्षक वर्ग-3 तथा बीएलओ राजकुमारी सिंह को एसआईआर कार्य अंतर्गत गणना पत्रक का वितरण एवं डिजिटल जांच का दायित्व सौंपा गया था, किन्तु उनके द्वारा उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फेक दिया

गया एवं कोई कार्य नहीं किया गया है।

जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा

कलेक्टर ने दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता करने और निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 (वर्गाकरण एवं अपील), नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर में नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

बीएलओ को लगाने पड़ रहे कई चक्कर



जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 के बाद जुड़े हैं, खासकर ऐसी महिलाएं जिनका विवाह 2003 के बाद हुआ है उन्हें मायके पक्ष से माता-पिता के वोटर आईडी कार्य में दर्ज इपिक नंबर, भाग संख्या व विधानसभा की जानकारी मंगानी पड़ रही है। जानकारी के अभाव व जागरूक न होने की वजह से यह जानकारी खासकर ग्रामीण नहीं जुटा पा रहे हैं। बीएलओ को कई बार मतदाताओं के घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे गणना पत्रकों की वापसी व फीडिंग की प्रगति प्रभावित हो रही है।

आसानी से नहीं मिल पा रही जानकारी

बीएलओ को माने तो एक मतदाता के यहां आधे घंटे से ज्यादा का समय पूरी प्रक्रिया में लग रहा है। इस बीच 2003 के बाद विवाह होकर आई महिला के गणना पत्रक को भरने में तो और ज्यादा समस्या होती है। मायके पक्ष का इपिक नंबर, भाग संख्या व विधानसभा सहित अन्य जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। समझाने के बाद भी वह जानकारी जुटाने में उन्हें दो से तीन दिन का समय लग जा रहा है। ऐसे में गणना पत्रक वापसी में काफी समय लग रहा है।



ट्रैफिक मित्र अब बनेंगे आपदा मित्र

ब्लैक स्पॉट पर घायलों को तुरंत मिलेगी सहायता

अनूपपुर नवभारत 19 नवंबर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को शुरुआती मिनटों में जीवन रक्षक सहायता मिल सके, इसके लिए गुरुवार को अनूपपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट के आसपास रहने वाले ट्रैफिक मित्रों को सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण डॉक्टरों का विशेषज्ञ

टीम ने कराया। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टरों ने दुर्घटना स्थल पर घायल की स्थिति पहचानने, प्राथमिक उपचार देने और सीपीआर की सही तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया। साथ ही प्रतिभागियों को बताया गया कि गंभीर रूप से घायल को अस्पताल ले जाते समय किन सावधानियों का पालन जरूरी है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा : एसपी

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देश पर आयोजित सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट का व्यावहारिक प्रशिक्षण का उद्देश्य जिले में एक प्रशिक्षित और संवेदनशील ट्रैफिक मित्र टीम तैयार हो, जो दुर्घटना होते ही तत्काल सहायता पहुंचाकर लोगों की जान बचा सके। एसपी ने बताया कि अनूपपुर पुलिस का लक्ष्य है कि जिले के प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर ऐसे प्रशिक्षित 'आपदा मित्र' मौजूद रहें। जो आपात स्थिति में समय से कार्रवाई कर घायल व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आ रहे जानवर

अब बिजुरी में चहलकदमी करता दिखा भालू, लोगों में दहशत

अनूपपुर नवभारत 19 नवंबर। जिस तरह इसनाओं की पहुंच जंगल तक पहुंच रही है, जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे आए दिन वन्यजीव भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि मानव और उनके बीच द्वन्द्व बढ़ता जा रहा है। जिले में खासकर कोयलाल में प्रतिदिन भालूओं की चहलकदमी हो रही है। मंगलवार-बुधवार की रात्रि बिजुरी नगर पालिका क्षेत्र में एक भालू चहलकदमी करते लोगों ने देख विडियों बनाकर सोशल मिडिया में डाला। आबादी क्षेत्रों में लगातार भालूओं की आवाजाही व वन विभाग की निष्क्रियता से स्थानीय



लोगों में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है।

कचरे में खाना ढूंढ रहा था

बिजुरी नगर पालिका क्षेत्र में एक भालू वार्ड नंबर 7 में चहलकदमी करते देखा गया। इससे पूर्व 18 नवंबर को जिले के नगर परिषद डोला के वार्ड क्रमांक 4 में भी एक घर के पीछे भालू देखा गया था। जहां भूख से बेहाल एक भालू रहवासी जगह पहुंच गया और कचरे में खाना ढूंढकर अपनी भूख शांत करता दिखा।

वन विभाग नहीं कर रहा ठोस कार्यवाही

भालू जमुना कॉलोनी, बिजुरी और नगर परिषद डोला में भालू का विचरण लगातार जारी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वन विभाग इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है। इस मामले में डीएफओ विपिन पटेल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।

एक नजर में

न्यायाधीश के घर हमले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

कोतमा 19 नवंबर। जिले के कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छबड़ा के घर 25 अक्टूबर की रात पत्थर मारने एवं जान से मारने की धमकी देने मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा गंगाचरण दुबे की अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजक संतोष सोनी ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी संतोष रजक, प्रियायु सिंह और संदीप कुमार चौरसिया की पृथक-पृथक परसूत प्रथम नियमित जमानत अर्जियों को निस्त कर दिया। अभियोजन ने बुधवार को बताया कि जिले के भालूमाड़ा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छबड़ा के शासकीय आवास पर 25 अक्टूबर की रात्रि तीन आरोपियों ने पत्थर मारने एवं जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट थाना भालूमाड़ा में अपराध भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धारा के तहत पंजीबद्ध किया गया था।



नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार

कोतमा 19 नवंबर। थाना प्रभारी भालूमाड़ा विपुल शुक्ला ने बताया कि गंभीर अपराध में दो माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना भालूमाड़ा में बीएएस एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी विनोद कुमार चौधरी घटना के दिनांक से ही फरार था। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने अपनी ही सौतेली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा धिनौना कृत्य किया था। घटना सामने आने के बाद से आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता फिर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी भालूमाड़ा के कुशल नेतृत्व में आरोपी की तलाश तेज की गई, जिसके तहत लगातार दो महीनों तक सघन प्रयास किए गए। 19 नवंबर को पुलिस टीम ने आरोपी विनोद चौधरी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

राजस्व लक्ष्य हासिल करने के कार्य को प्राथमिकता दें : कलेक्टर

अनूपपुर नवभारत 19 नवंबर। जिला स्तरीय सीएसआर मद एवं जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक बुधवार को कलेक्टर हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शासन द्वारा 332 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2024-25 के 307 करोड़ रुपये की तुलना में 25 करोड़ अधिक है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएसआर मद का उपयोग सामाजिक हितों से जुड़े कार्यों में प्राथमिकता के साथ किया जाए। कलेक्टर ने एसईसीएल सोहागपुर, जमुना-कोतमा और हसदेव क्षेत्र के जनरल मैनेजरों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व वसूली कार्यों में प्राथमिकता लाई जाए। साथ ही, आरआरसी के लंबित प्रकरणों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की स्थिति की जानकारी ली और राजस्व, खनिज तथा पुलिस विभाग का संयुक्त दल गठित कर सतत अभियान चलाते हुए कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

नुककड़ नाटक के जरिये लोगों को किया जागरूक

स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नुककड़ नाटक व कठुतली का आयोजन

अमरकंटक नवभारत 19 नवंबर। अमरकंटक नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण 2025-26 को बुधवार नगर के प्रमुख चौराहों पर नुककड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से नगर के जनता जनार्दन को स्वच्छता और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक किया गया।

नुककड़ नाटक के दौरान नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखाई। कलाकारों ने सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग डस्टबिन में डालने, घरों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में डाले तथा समय पर नगरपालिका की गाड़ी में डाले तथा नगर की साफ-सफाई बनाए रखने का संदेश दिया गया।

सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रखें

नुककड़ नाटक के माध्यम से

स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नुककड़ नाटक व कठुतली का आयोजन

नुककड़ नाटक के माध्यम से नगर के जनता जनार्दन को स्वच्छता और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक किया गया।

नुककड़ नाटक के दौरान नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखाई। कलाकारों ने सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग डस्टबिन में डालने, घरों से



नुककड़ नाटक के माध्यम से नगर के जनता जनार्दन को स्वच्छता और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक किया गया।

नुककड़ नाटक के दौरान नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखाई। कलाकारों ने सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग डस्टबिन में डालने, घरों से

नगर पालिका की ओर से नागरिकों से अपील भी किया कि सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रखें, कचरे को सड़क या नाले में न फेंके, स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर को शीर्ष स्थान दिलाने में सहयोग दें। अपने घर, मोहल्ले और पूरे नगर को स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाए रखने में सहयोग करें। अभियान का उद्देश्य नगरवासियों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2025-26 में अमरकंटक को उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल कराना है।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों को गंभीरता से लें

कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

अनूपपुर नवभारत 19 नवंबर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी प्रकरणों का स्वयं अनुसरण करें तथा



शिकायतकर्ता से सीधा संवाद स्थापित करें। शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए अधिकारी अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय जिम्मेदार अधिकारी

नियमित मॉनिटरिंग करते हुए हेल्पलाइन प्रकरणों की ग्रैडिंग सुधारने पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य विभाग सहित कई विभागों की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की।

आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की

उन्होंने योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन, बजट उपयोग, हितग्राही योजनाओं की स्थिति और आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचे, यह सभी अधिकारियों को प्राथमिक जिम्मेदारी है। विभागों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा करें और आवश्यकतानुसार फॉलोअप/विजिट कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें।

पत्रकारों को आपात स्थिति में मिलेगी आर्थिक सहायता

बीमारी, दुर्घटना व मृत्यु होने पर सरकार देगी मद, पत्रकारों के लिए लाभकारी योजना

अनूपपुर नवभारत 19 नवंबर। केंद्र सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में पिछले चार वर्षों से 'पत्रकार कल्याण योजना' संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मीडिया कर्मियों और उनके आश्रितों को आपात स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना विशेष रूप से उन पत्रकारों के लिए अत्यंत लाभकारी है जिन्हें उपचार, दुर्घटना या



पारिवारिक संकट के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा की है कि जिले के पत्रकारों को योजना की जानकारी समय पर उपलब्ध कराते हुए उन्हें आवेदन प्रक्रिया में हर संभव सहायता दी जाए।

कौन हैं पात्र?

राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नलीनकांत बाजपेई ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पत्रकार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को योजना के पात्र हैं। जो पत्रकार मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब मीडिया से कम से कम 5 वर्ष से निरंतर जुड़े हुए हैं, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। फ्रीलांस पत्रकार भी इसमें शामिल हैं।

उर नहीं किसी का कोतमा से प्रतिदिन ट्रकों में भरकर छत्तीसगढ़ जा रही धान, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की चुप्पी, माफिया सक्रिय

कोतमा नवभारत 19 नवंबर। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवैध धान की ढुलाई खुलेआम होने के बावजूद जिला प्रशासन और कलेक्टर द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी नहीं, रात में वाहनों की चेकिंग नहीं, गोदामों की नियमित जांच नहीं और परिवहन व्यवस्था की निगरानी न होना प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि कलेक्टर की यह चुप्पी धान माफिया के लिए 'ग्रीन सिग्नल' बन चुकी है। अनूपपुर,



कोतमा, बिजुरी, आमाडांड, निगवानी, कोठी, छाता, भालूमाड़ा, चोलना, जैतहरी, वैकुंठनगर और अमरकंटक क्षेत्र में प्रतिदिन समर्थन मूल्य से कम दाम पर धान खरीदा जा रहा है, जिसे रात होते ही ट्रकों में भरकर

खुले रास्तों से सीधे छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता है।

खरीदा गया धान पहले गोदामों में भर दिया जाता है

बताया जा रहा है कि अनूपपुर से छत्तीसगढ़ तक अवैध धान परिवहन का रूट पूरी तरह सक्रिय

छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों की ओर धड़ल्ले से भेज दिया जाता है। स्थिति यह है कि धान परिवहन के लिए ट्रकों की लंबी कतारें रात के

तो आधे से अधिक धान छग चली जायेगी

जिला प्रशासन द्वारा समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो जिले में सरकार धान खरीदी आरंभ होने से पहले ही आधे से अधिक किसान अपना धान छत्तीसगढ़ भेज देंगे, जिससे जिले में धान खरीदी का लक्ष्य अधूरा रह जाने की आशंका है। स्थानीय नागरिकों व कृषकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तुरंत नाकेबंदी की जाए, रात में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, गोदामों की जांच की जाए और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों व धान माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश का अनाज दूसरे राज्यों में न जा सके और किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

